www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 169 | जौनपुर मंगलवार, 03 फरवरी 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

बजट 2026 में भारत के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रावधान किए गए : अनुप्रिया पटेल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रविवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2026 में भारत के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।पटेल ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में स्वास्थ्य, फार्मा और रसायन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। पटेल ने कहा, "भारत आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ चुका है और आज कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है।" 10,000 करोड़ रुपए के बायोफार्मा शक्ति मिशन की सराहना करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि इससे "भारत को आने वाले समय में बायोफार्मा का विनिर्माण केंद्र बनने में मदद मिलेगी, जिसका अर्थ है कि यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।"पटेल ने कहा कि आने वाले समय में संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों की बढ़ती आवश्यकता और मांग को देखते हुए, अगले पांच वर्षों में देश में 10,000 संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों का सृजन किया जाएगा और नए संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था देखभाल को मजबूत करने के लिए, इस बजट के प्रावधानों के तहत एक लाख बहु–कुशल देखभाल पेशेवरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा मूल्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, देश में पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए सपनों का बजट : वीरेंद्र सचदेवा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार को केंद्रीय बजट 2025–26 में स्मार्टफोन पर दी गई रियायतों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे युवाओं को कई लाभ मिलेंगे और मध्यम वर्ग नए करों से सुरक्षित रहेगा।सचदेवा ने दिल्ली भाजपा राज्य कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 13वें बजट प्रस्ताव को सुना। उन्होंने कहा कि यह बजट, जो खेल और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देता है, युवा हितैषी है। सचदेवा ने कहा, "बजट 2026, जो निर्माण उद्योग, पर्यटन, तीर्थ स्थलों के विकास और चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देता है, युवा भारत को नई उड़ान देगा।" उन्होंने कहा कि यह दिल्ली में नए केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर, कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है, और यह जनता के प्रति सरकार की जिम्मेदारी को पूरा करता है।सचदेवा ने कहा कि दिल्ली और अन्य शहरी क्षेत्रों में विकास के अगुआ निजी बिल्डरों के ऋणों के लिए सुरक्षा कवर प्रदान करके भारत सरकार ने तीर्थ स्थलों के विकास को भी गति दी है। इससे निर्माण उद्योग को लाभ होगा और भवन निर्माण कार्य में वृद्धि होगी। बजट 2026 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने हेतु चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दिया है, जिससे चिकित्सा क्षेत्र में हजारों रोजगार सृजित होंगे।

बजट 2026 से बदलेगी युवाओं-महिलाओं की तकदीर, गिनाए कई बड़े फायदे : सीएम योगी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्रीय बजट आम जनता पर केंद्रित है और महिला–केंद्रित है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य 2047 तक षविकसित भारतष के मिशन को हासिल करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ने शविकसित भारतश का रोडमैप तैयार करते हुए आज केंद्रीय बजट पेश किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को बजट दिशा–निर्देशों के मार्गदर्शन और देखरेख के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी इस बजट को पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूं। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि बजट में सात रेल गलियारों के निर्माण सहित अवसंरचना विकास के लिए 12 लाख रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के 145 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं को दर्शाता है। यह शविकसित भारतश के दृष्टिकोण और मिशन का प्रतीक है। अवसंरचना विकास के लिए पूंजीगत व्यय हेतु 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिसमें सात रेल गलियारों के लिए भी प्रावधान शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 में विभिन्न क्षेत्रों और सुधारों को शामिल किया गया है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह बजट कामकाजी महिलाओं पर केंद्रित है, विशेष रूप से छात्रावासों के विकास पर, साथ ही गणित, विज्ञान, सांख्यिकी और उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए छात्रावासों के विकास पर भी। इससे देश के युवाओं के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि युवाओं को हर क्षेत्र में अवसर मिलें। इसके साथ ही, इसमें कई क्षेत्रों और सुधारों को शामिल किया गया है जो आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाएंगे। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

आईसीजी विश्वास की दीवार, ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका को भी सराहा : राजनाथ सिंह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय तटरक्षक बल ने पिछले 50 साल में समुद्री सुरक्षा में अहम भूमिका निभाई है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) की 50वीं स्थापना दिवस पर देश की रक्षा में अहम भूमिका के लिए आईसीजी की तारीफ की। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने के लिए सराहना भी की। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर में तटरक्षक बल ने अग्रिम रणनीतिक तैयारी की, पश्चिमी तट पर निगरानी बढ़ाई और समुद्री और खाड़ी क्षेत्रों में उच्च सतर्कता बनाए रखी। इस अवसर पर सिंह ने कहा कि यह ऑपरेशन सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतरीन समन्वय का उदाहरण था और यह साबित करता है कि आईसीजी वास्तव में हमारी समुद्री सीमाओं का अग्रिम रक्षक है। 1 फरवरी 1977 को केवल 7 सतही जहाजों के साथ शुरू हुआ आईसीजी अब 155 जहाजों और 80 हवाई जहाजों का आधुनिक बल बन गया है। 2030 तक आईसीजी का लक्ष्य 200 जहाज और 100 हवाई जहाज हासिल करना है। आईसीजी ने अब तक समुद्र में 11,800 से अधिक जीवन बचाए हैं और आतंकवाद, हथियार और मानव तस्करी रोकने से लेकर समुद्री सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं में बचाव और समुद्री प्रदूषण नियंत्रण तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिंह ने कहा कि आईसीजी विश्वास की दीवार है, जो भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है।

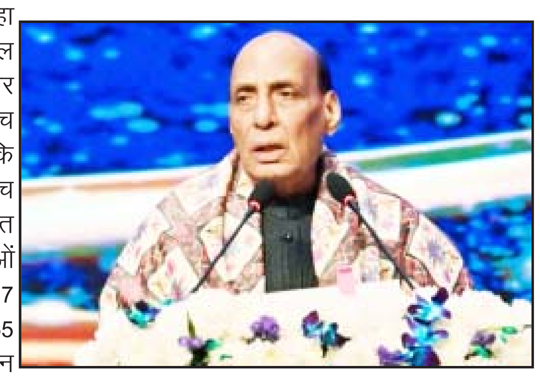

लोकसभा में तेजस्वी सूर्या की स्पीच पर कांग्रेस का हंगामा, अमित शाह ने एक लाइन में किया चुप

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा कांग्रेस को चुनौती देने से हंगामा मच गया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हस्तक्षेप करना पड़ा। तेजस्वी सूर्या ने अपने संबोधन में कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि उसकी सरकार ने भारत की सभ्यतागत परंपराओं का कभी जिक्र नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को पूर्व राष्ट्रपतियों के भाषणों को पढ़ते हुए ऐसा कोई उदाहरण दिखाने की चुनौती दी। सूर्या ने आरोप लगाया कि स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर दिए गए संक्षिप्त भाषण के अलावा, कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में भारत की संस्कृति, परंपरा, सभ्यतागत मूल्यों और परंपराओं का कोई जिक्र नहीं हुआ। यह देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सूर्या ने आगे कहा कि वहीं, 2014 में प्रधानमंत्री ने परंपरा और प्रौद्योगिकी में सुधार का वादा किया था। उस वादे को पूरा करने वाले एकमात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सूर्या की टिप्पणियों का कांग्रेस नेताओं ने तुरंत विरोध किया, जिसके बीच कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने सूर्या का खंडन किया। उन्होंने कहा कि केरल विधानसभा के पूर्व सदस्य पीटी थॉमस ने श्री नारायण गुरुदेव के बारे में बहुत कुछ कहा है और सूर्या की टिप्पणियों को उनका अपमान बताया। ईडन ने कहा कि पीटी थॉमस ने श्री नारायण गुरुदेव के बारे में बहुत कुछ कहा है। तेजस्वी सूर्या यह दावा कैसे कर सकते हैं कि किसी भी कांग्रेस नेता ने भारतीय परंपराओं के बारे में बात नहीं की है? उन्होंने श्री नारायण गुरुदेव का अपमान किया है। ईडन के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद ष्संसद पर नहीं, केरल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

पीएम मोदी द्वारा हलवारा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का दौरा किया और हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा, आदमपुर रखा। पीएम मोदी ने पंजाब के लुधियाना स्थित हलवारा हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती के अवसर पर पंजाब आए थे। आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर इस पूजनीय संत और समाज सुधारक को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, जिनकी समानता, करुणा और मानवीय गरिमा की शिक्षाएं भारत के सामाजिक मूल्यों को प्रेरित करती रहती हैं। पीएम द्वारा हलवारा हवाई अड्डे पर उद्घाटन किया गया टर्मिनल भवन राज्य के लिए एक नया प्रवेश द्वार स्थापित करेगा, जो लुधियाना और उसके आसपास के औद्योगिक और कृषि प्रधान क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेगा। लुधियाना जिले में स्थित हलवारा में भारतीय वायु सेना का एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्टेशन भी है। इस दौरान मोदी ने कहा कि आज माघ पूर्णिमा की पवित्र तिथि है। श्री गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती का पावन अवसर है। इस पुण्य पर्व पर आज मुझे आप सभी के बीच आने का सौभाग्य मिला है। मैं इस पवित्र मंच से श्री गुरु रविदास जी को प्रणाम करता हूं और आप सभी को और सभी देशवासियों को संत रविदास जयंती और माघ पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा रिश्ता श्री गुरु रविदास जी की जन्मभूमि काशी से है। काशी के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिए और सांसद के रूप में काशी की सेवा करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। मैं जब भी सीर गोवर्धनपुर जाता हूं, बड़ी संख्या में मुझे पंजाब के भाई बहनों से मिलने का भी सौभाग्य मिलता है। मैं इस बार संत रविदास जी की प्रेरणा भूमि पंजाब की वीर भूमि पर आया हूं। मैं मानता हूं कि ये श्री गुरु रविदास जी की ईच्छा है और मेरा बहुत सौभाग्य है। मैं इस आयोजन में निमंत्रित करने के लिए डेरा सचखंड बल्ला का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि समाज सेवा के क्षेत्र में डेरा सचखंड बल्लां के कार्य बहुत सराहनीय रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े अनेक कार्य पूज्य संत श्री निरंजन दास जी महाराज के मार्गदर्शन में अविरत हो रहे हैं।

सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण पर सामना का तीखा प्रहार

नई दिल्ली, (एजेंसी)। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम घट रहे हैं, उन्होंने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (छब्) के दिग्गज नेता और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का आनन–फानन में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेना एक नए राजनीतिक विवाद को जन्म दे चुका है। सोमवार को शिवसेना (न्ठज) के मुखपत्र 'सामना' में प्रकाशित संपादकीय ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राकांपा के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्षी शिवसेना (उबाठा) ने सोमवार को दावा किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के पीछे का "सूत्रधार" भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेतृत्व है। सुनेत्रा पवार ने अपने पति अजित पवार के निधन के बाद उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के मुखपत्र 'सामना' में प्रकाशित संपादकीय में यह भी आरोप लगाया गया है कि भाजपा नेतृत्व और राकांपा नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल राकांपा के दोनों धड़ों का विलय नहीं चाहते हैं। पुणे जिले के बारामती में एक विमान दुर्घटना में राकांपा नेता एवं उप मुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की मौत के ठीक तीन दिन बाद सुनेत्रा पवार ने शनिवार को राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिससे तेजी से घटे इस घटनाक्रम को लेकर कुछ वर्गों से आलोचना भी हुई। राकांपा (शरदचंद्र पवार) प्रमुख और अजित पवार के चाचा शरद पवार ने शनिवार को दावा किया कि उन्हें सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण के बारे में "कोई जानकारी नहीं" थी। 'सामना' में कहा गया है कि महाराष्ट्र के सामने सवाल यह है कि सुनेत्रा पवार ने किसकी इच्छा पर उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली, क्योंकि न तो राकांपा (शप) अध्यक्ष शरद पवार, न ही उसकी कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और न ही पवार परिवार के किसी सदस्य को इसकी जानकारी थी। संपादकीय में यह भी कहा गया कि सुनेत्रा पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बारामती से मुंबई रवाना होने का जरा–सा भी संकेत नहीं दिया था। उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना (उबाठा) ने दावा किया।

असम में सत्ता में बैठे व्यापारी, केंद्र ने आदिवासियों को हाशिये पर धकेल दिया : हेमंत सोरेन

असम, (एजेंसी)। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को केंद्र और असम में सत्ता में बैठे लोगों पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वे "राजनीतिज्ञ नहीं, बल्कि व्यापारी" हैं और आदिवासी समुदाय को हाशिये पर धकेलकर केवल संसाधनों के दोहन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। असम के तिनसुकिया में आदिवासियों की एक सभा को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि चुनावी राज्य असम में चाय जनजातियों को राज्य की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने के बावजूद उपेक्षित किया जा रहा है। सोरेन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपने संबोधन का हवाला देते हुए लिखा, "देश और असम में सत्ता में बैठे लोग राजनीतिज्ञ नहीं, व्यापारी हैं। वे सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। ऐसे में आदिवासियों का एकजुट रहना जरूरी है।" उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज आत्मसम्मान के साथ जीने वाला समाज है और आंखों में आंखें डालकर चलने में विश्वास रखता है। सोरेन ने कहा, "इन्हीं लोगों (केंद्र और असम में सत्ता में बैठे लोग) ने मुझे जेल भेजा था। मैंने तब कहा था कि अगर मैं आगे आया, तो उनकी गले की हड्डी बनूंगा।

रेलवे को मिला 2.78 लाख करोड़ : अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली, (एजेंसी)। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संसद में पेश किया गया केंद्रीय बजट विकास भारत का खाका प्रस्तुत करता है और 2,78,000 करोड़ रुपये का रेल बजट इसी दिशा में एक स्पष्ट कदम है। एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में वैष्णव ने कहा कि आज सात नए हाई–स्पीड कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। सूचना एवं प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी रहे वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय बजट युवाओं और महिलाओं को समर्पित है और देश के प्रति कर्तव्य की भावना से प्रेरित है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज का बजट हमारे देश के युवाओं को समर्पित है। यह हमारे देश में महिलाओं की शक्ति को समर्पित है। और यह कर्तव्य की भावना से प्रेरित है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना से प्रेरित है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे देश में शसबका साथ, सबका विकासश हो। बजट में विकास भारत का रोडमैप भी निर्धारित किया गया है। आज का 2,78,000 करोड़ रुपये का रेलवे बजट स्पष्ट रूप से इसी दिशा में एक कदम है... आज सात नए हाई–स्पीड कॉरिडोर की घोषणा की गई है। ये हाई–ेचममक कॉरिडोर यात्रा के समय को काफी कम कर देंगे, जिससे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने आगे कहा कि चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद दृ ये दक्षिणी त्रिकोण दृ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास को गति प्रदान करेंगे। यह सभी पांचों दक्षिणी राज्यों के लिए एक बड़ी जीत होगी। वैष्णव ने कहा कि लगभग 4,000 किलोमीटर लंबे हाई–स्पीड कॉरिडोर 16 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद, मुंबई, पुणे और हैदराबाद भी प्रमुख आर्थिक कॉरिडोर बन जाएंगे।

पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा यह बजट : भूपेंद्र पटेल

गुजरात, (एजेंसी)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को कहा कि केंद्रीय बजट में गरीबों, युवाओं, खाद्य प्रदाताओं, नारी शक्ति और दिव्यांगजनों को भारत के विकास एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास और आत्मनिर्भर राष्ट्र के दृष्टिकोण को दर्शाता है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पटेल ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी ने हमेशा आम जनता को प्राथमिकता दी है। उनके नेतृत्व में यह बजट एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए सुधार की रफ्तार को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने लगातार नौवीं बार बजट पेश करने पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इसमें ज्ञान, गरीबों, युवाओं, खाद्य प्रदाताओं, नारी शक्ति और दिव्यांगजनों के स्तंभों को मजबूत किया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा कि बजट में ऐसा दृष्टिकोण अपनाया गया है जिससे समाज के हर वर्ग को "सौना साथ, सौना विकास" के मंत्र के अंतर्गत शामिल किया जा सके। पटेल ने कहा कि बुनियादी ढांचे, उद्योगों, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर और डेटा केंद्रों पर विशेष ध्यान देने से आर्थिक विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, एमएसएमई पर जोर देने से लघु और सूक्ष्म उद्योगों को काफी लाभ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन से गुजरात के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने रसद और कनेक्टिविटी पर प्रकाश डालते हुए कहा, ष्डांकुनी से सूरत तक समर्पित माल ढुलाई गलियारा राज्य के व्यापार, उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र के लिए तेज रसद सेवाएं प्रदान करेगा। उन्होंने आगे कहा कि वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए घोषित छह योजनाओं से गुजरात के वस्त्र क्षेत्र को लाभ होगा, जबकि तीन रासायनिक पार्कों की घोषणा और जैव–फार्मा उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन इन क्षेत्रों में गुजरात की स्थिति को मजबूत करेगा।

संपादकीय

कांग्रेस की समस्या

बचाओ या वापस लाओ जैसे नारे लोगों का ध्यान खींचने के लिहाज से हमेशा अपर्याप्त साबित हुए हैं। कांग्रेस की समस्या यह है कि हाल–फिलहाल में वह भविष्य का कोई सपना या लोक–लुभावन कार्यक्रम पेश करने में नाकाम रही है। मजदूर अधिकार के सवाल पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस की सही दिशा में पहल है, बशर्ते यह मुद्दा उसकी क्षणिक चिंता बन कर ना रह जाए। कामकाजी वर्ग की बढ़ती मुश्किलें और उसके घटते अधिकार आज असल मुद्दे हैं, जिनकी मुख्यधारा राजनीति में मजबूत वकालत की जरूरत है। मनरेगा खत्म कर उसकी जगह जी राम जी कानून लागू करने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के बाद कांग्रेस ने इस पर ध्यान दिया है। चूंकि मनरेगा को कांग्रेस नेतृत्व अपनी बड़ी उपलब्धि मानता था, इसलिए उस पर हुए प्रहार से वह भी विचलित हुआ। तब पार्टी ने श्मनरेगा बचाओश आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। अब पार्टी उसे मजदूर अधिकार के बड़े दायरे से जोड़ने का संकेत दे रही है। इस मसले पर पार्टी समग्र सोच विकसित कर सके और उसके आधार पर संगठन एवं संघर्ष की दीर्घकालिक योजना बनाए, तो उससे कांग्रेस को आज के दौर में एक खास पहचान मिल सकती है। मगर पार्टी नेतृत्व की मुश्किल यह है कि वह संयम के साथ किसी एक मुद्दे पर नहीं टिकता। और जो भी मुद्दा वह उठाता है, उसके पीछे मकसद अपनी पूर्व सरकारों के रिकॉर्ड को मोदी सरकार पर बेहतर दिखाने तक सीमित रह जाता है। राफेल से लेकर ए–2 (यानी दो घरानों की मोनोपॉली) पर आक्रामक रुख अपनाने के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी जातीय जनगणना एवं 1990 के दशक के मंडल–कालीन विमर्श में जा सिमटे। उसी क्रम में श्संविधान बचाओश का झंडा उन्होंने उठाया। फिर श्वोट चोरीश उनका पसंदीदा मसला बना। अब मनरेगा ही वापसी उनका प्रिय विषय बना है। जबकि समझने की बात यह है कि श्बचाओश या श्वापस लाओश जैसे नारे लोगों का ध्यान खींचने के लिहाज से हमेशा अपर्याप्त साबित हुए हैं। कांग्रेस की समस्या यह है कि हाल के दशकों में वह भविष्य का कोई सपना या लोक–लुभावन कार्यक्रम पेश करने में नाकाम रही है। ऐसे में आम जन को उसका एजेंडा नकारात्मक मालूम पड़ता है। पार्टी के मजदूर अधिकार सम्मेलन को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाएगा। सवाल यह है कि क्या यहां से कांग्रेस कोई सकारात्मक सोच देश के सामने रख पाएगी

भारत ने बिछाई बड़ी कूटनीतिक बिसात तो सौदेबाजी की मेज पर भागता हुआ आया अमेरिका

नीरज

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की अमेरिका यात्रा ऐसे समय हो रही है जब वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा और व्यापारिक खींचतान एक दूसरे में उलझ चुकी हैं। जयशंकर की यह यात्रा आपूर्ति शृंखला, दुर्लभ खनिज, रक्षा सहयोग और व्यापार समझौते पर नए संतुलन की तलाश है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की पहल पर आयोजित महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में जयशंकर की भागीदारी इस बात का संकेत है कि आने वाले दशक की शक्ति राजनीति खनिज, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा के ईर्द गिर्द घूमेगी। इस यात्रा का पहला स्पष्ट लक्ष्य महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करना है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब यह समझ चुकी हैं कि दुर्लभ खनिजों पर निर्भरता केवल आर्थिक विषय नहीं बल्कि सामरिक प्रश्न है। चीन जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता कम करने की मुहिम में भारत को एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। भारत की खनिज क्षमता, विशाल बाजार और तकनीकी मांग उसे इस खेल का केन्द्रीय खिलाड़ी बनाती है। जयशंकर की यह यात्रा सात महीने बाद उनकी पहली द्विपक्षीय अमेरिका यात्रा है। पिछली यात्रा उस समय हुई थी जब अमेरिका ने भारत पर कड़े शुल्क नहीं लगाए थे। इन महीनों में बहुत कुछ बदल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद शुल्क को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क और रूस से तेल खरीद पर दंडात्मक शुल्क ने संबंधों में कड़वाहट घोली। अब संकेत मिल रहे हैं कि वाशिंगटन नरमी दिखा सकता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि रूस से तेल खरीद घटने पर अतिरिक्त शुल्क हटाने का रास्ता है। साथ ही वेनेजुएला से तेल खरीद फिर शुरू करने की अनुमति का संदेश भी दिया गया है। यह सब केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि वार्ता की मेज पर सौदेबाजी के पत्ते हैं। दिलचस्प यह है कि इसी बीच भारत ने 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौता पूरा कर लिया। इसने अमेरिका को यह संदेश दिया कि नई दिल्ली विकल्प तलाशने में सक्षम है। अटलांटिक परिषद से जुड़े विशेषज्ञ मार्क लिंस्काट का आकलन है कि भारत यूरोप समझौता अमेरिका भारत व्यापार वार्ता को तेज कर सकता है। साफ है कि वाशिंगटन भारत को खोना नहीं चाहता। वैसे भी भारत और अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व की हालिया बातचीत और सार्वजनिक बयानों से यह आभास भी मजबूत हो रहा है कि दोनों देश लंबित व्यापार समझौते को अब अधिक देर तक टालना नहीं चाहते। पिछले महीनों में फोन पर हुई वार्ताओं, मंत्रिस्तरीय संपर्क और समान हितों पर दिए गए जोर से यह संकेत मिलते हैं कि माहौल को जानबूझकर सकारात्मक बनाया जा रहा है। ऐसे में जयशंकर की अमेरिका यात्रा को केवल खनिज या सामरिक चर्चा तक सीमित नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे संभावित व्यापार समझौते की राह साफ करने वाली पहल के रूप में भी समझा जा रहा है। कूटनीतिक गलियारों में यह धारणा बन रही है कि यदि इस यात्रा में मुख्य अड़चनों पर सहमति का रास्ता निकलता है तो यह आगे की औपचारिक वार्ता के लिए हरी झंडी जैसा होगा, जिसके बाद मोदी सरकार अंतिम राजनीतिक स्वीकृति देकर समझौते पर मुहर लगा सकती है। यानी यह दौरा भविष्य के बड़े आर्थिक फैसले की भूमिका भी लिख सकता है। हम आपको यह भी बता दें कि अपनी यात्रा से पहले जयशंकर ने भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। उनके साथ अमेरिकी संसद के सदस्य जिमी पैट्रोनिस, माइक रोजर्स और एडम स्मिथ भी मौजूद रहे। बातचीत में व्यापार, रक्षा सहयोग, महत्वपूर्ण खनिज, हिंद प्रशांत क्षेत्र और यूक्रेन संघर्ष जैसे विषय शामिल रहे। यह केवल शिष्टाचार भेंट नहीं बल्कि जमीन तैयार करने वाली बातचीत थी। गोर ने भारत को अमेरिका का अहम भागीदार बताया और साझा सामरिक हितों पर जोर दिया। साथ ही अमेरिकी संसदीय दल की जनवरी में नई दिल्ली यात्रा भी रक्षा तकनीक सहयोग, सह उत्पादन और सह विकास पर केंद्रित रही। संदेश साफ है कि रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग संबंधों की रीढ़ बन सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम को भारत के केंद्रीय बजट की घोषणाओं से जोड़कर देखिये। मोदी सरकार ने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज संपन्न राज्यों में दुर्लभ खनिज गलियारे बनाने का प्रस्ताव रखा है। खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और निर्माण को बढ़ावा देने की योजना सीधे उसी दिशा में जाती है जिस पर अमेरिका और उसके सहयोगी काम कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर अभियान के लिए ये खनिज अनिवार्य हैं। बैटरी भंडारण के लिए लिथियम आयन कोश निर्माण, सीर कांच के लिए सोडियम एंटिमोनेट, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आयातित सामान पर मूल शुल्क छूट, मिश्रित सीएनजी पर उत्पाद शुल्क गणना से जैव गैस को बाहर रखना और बैटरी भंडारण परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर सहायता को पांच गुना बढ़ाना दिखाता है कि भारत ऊर्जा और प्रौद्योगिकी की नई दौड़ के लिए तैयारी कर रहा है। 2030 तक पांच सौ गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा और 2047 तक सौ गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य भारत की नई सामरिक दिशा है। निजी भागीदारी खोलने वाला परमाणु ऊर्जा कानून भी इसी कड़ी का हिस्सा है। सच यह है कि दुनिया नए शीत युद्ध जैसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां गोलियों से ज्यादा खनिज, चिप और ऊर्जा की आपूर्ति शृंखला ताकत तय करेगी। जयशंकर की यात्रा को केवल कूटनीतिक दौरा समझना भूल होगी। यह भारत की बहुस्तरीय चाल है। एक ओर अमेरिका से तनाव घटाना, दूसरी ओर अपने हितों पर अडिग रहना, और साथ साथ यूरोप, रूस तथा अन्य साझेदारों के साथ संतुलन बनाए रखना आसान नहीं। पर भारत अब रक्षात्मक नहीं, सौदेबाज की मुद्रा में दिख रहा है। अमेरिका को भी समझना होगा कि शुल्क की लाठी से साझेदारी नहीं चलती। यदि वह भारत को सचमुच चीन का विकल्प बनाना चाहता है तो भरोसा, प्रौद्योगिकी साझेदारी और बाजार पहुंच देनी होगी। भारत के लिए भी संदेश साफ है कि आत्मनिर्भर खनिज और सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र बनाए बिना कोई सामरिक स्वायत्तता संभव नहीं। बहरहाल, जयशंकर की कूटनीति की खासियत यही है कि वे मुस्कान के साथ कठोर संदेश देते हैं। अब देखना यह है कि वाशिंगटन इस संकेत को कितना समझता है। अभी जो तस्वीर उभर रही है वह बताती है कि नई दिल्ली ने खेल समझ लिया है और चाल चल दी है।

ऐतिहासिक फैसला करने का समय आ गया है

संतोष

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा बनाए गए नए नियमों पर फिलहाल रोक तो लगा दिया है लेकिन इसके बावजूद यह विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले यूजीसी द्वारा बनाए गए नियमों के खिलाफ अगड़ी जातियों के लोग सड़कों पर थे और अब इसके समर्थन में एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोग सड़कों पर हैं। विवाद चाहे किसी भी मुद्दे पर हो, यह तनाव लाता है और समाज की शांति को भंग करता है। इसलिए विवाद को टालने के बजाय हमेशा स्थाई समाधान को तलाशने के लिए काम करना चाहिए। सही मायने में देखा जाए तो यूजीसी नियमों पर मचे घमासान या यूं कहें कि ताजा विवाद ने दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश भारत को एक बड़ा मौका दे दिया है और हम अगर इस बार चूक गए तो फिर आने वाले कई दशकों तक यह विवाद देश और समाज की शांति को भंग करता रहेगा। सामान्य भाषा में कहे तो हमारे देश के संविधान ने भारत में रहने वाले सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से जुड़े हुए हो। भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत तो यही रहा है कि श्सौ दोषी भले छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए।श यह सिद्धांत हमें स्पष्ट तौर पर बताता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर पूरे समाज के भरोसे को बरकरार रखने के लिए यह सबसे अधिक जरूरी है कि किसी भी निर्दोष को किसी भी हालत में वर्ष, महीने, दिन और घंटे तो छोड़िए, एक सेकंड के लिए भी प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। इस कसौटी पर रखकर जब यूजीसी के नियमों को तौला जाता है तो यह साफ–साफ नजर आता है कि यूजीसी ने अपने नियम के जरिए भारत के लोकतांत्रिक और न्यायिक व्यवस्था के मूल सिद्धांत को ही कुचलने की तैयारी कर ली थी। कई लोग यह तर्क भी देते हुए नजर आए कि दुरुपयोग तो किसी भी कानून का हो सकता है। कुछ लोगों ने कई अन्य कानूनों के दुरुपयोग का उदाहरण दिया तो कुछ लोगों ने हजार वर्षों के शोषण का जिक्र करते हुए इसे सही ठहराया। हालांकि भारत के लोगों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि यह मामला सिर्फ अगड़ा बनाम पिछड़ा भर का नहीं रह गया है और इसे रहना भी नहीं चाहिए। आजादी के 75 वर्षों बाद अब यह सोचने का समय आ गया है कि क्या हमारी व्यवस्था कानून का पालन करने वाले निर्दोष लोगों के साथ न्याय कर पा रही है। यह आपको अजीब लगेगा लेकिन सही मायनों में अब हमें इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहिए कि आखिर बिना किसी सजा के लोगों को दिन, महीने, साल ही नहीं दशकों तक जेल की सलाखों के पीछे रखने के लिए जिम्मेदार कौन है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून, दहेज, महिला उत्पीड़न सहित उन तमाम कानूनों की समीक्षा करने का वक्त आ गया है जो पुलिस को बिना किसी जांच के गिरफ्तार करने का अधिकार देते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में बिना किसी सबूत के किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग हजारों वर्षों के शोषण की याद दिलाते हैं,उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि उनके स्तर को उठाने और भेदभाव खत्म करने के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है और देश का अगड़ा वर्ग भी पिछले कई दशकों से इसे स्वीकार कर चुका है। लेकिन किसी को भी इतना अधिकार तो नहीं दिया जाना चाहिए कि वो किसी और जाति, धर्म अथवा संप्रदाय के लोगों को बिना मतलब कानूनी विवाद में उलझा दें अथवा जेल भिजवा दें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि, लोग ना जाने क्यों इस तथ्य को भी भुला देते हैं कि हजार साल पहले की शासन व्यवस्था चाहे जैसी भी रही हो लेकिन इस देश में पिछले 75 वर्षों से लोकतंत्र है, संसद है, न्यायपालिका है और मीडिया भी है। अगर हजार साल पहले ऐसा कुछ हुआ भी होगा जिसका दावा आमतौर पर किया जाता है तो क्या उसका बदला अब एक आजाद लोकतांत्रिक देश में लेने की इजाजत दी जा सकती है। यह तो श्आंख के बदले आंखश लेने जैसा नियम लागू हो जाएगा। वाद–विवाद में तथ्यों और आंकड़ों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है लेकिन दुर्भाग्य से आज के माहौल में कोई इस पर बात ही नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है जैसे सब अपना–अपना दायरा पहले ही तय कर चुके हैं और कोई भी इससे

आगे जाना ही नहीं चाहता। शोषण कौन कर रहा है और शोषण किसका हो रहा है, यह तो किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के परसेप्शन के आधार पर तय नहीं हो सकता, इसकी गवाही तो सिर्फ और सिर्फ आंकड़ें ही दे सकते हैं और जैसे ही आप आंकड़ों को सामने रखते हैं तो सारी कहानी ही पलटी हुई नजर आती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बार–बार आबादी के बहाने इस विवाद को सुलगाने की कोशिश करने वाले ये भूल जाते हैं कि अगर आप बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो फिर संविधान निर्माताओं की भावना का सम्मान करते हुए ऐसे लोगों को जिनकी आबादी कम है, उन्हें तो कई तरह के विशेषाधिकार देने पड़ेंगे। इसलिए, इस विवाद को हमेशा–हमेशा के लिए खत्म करना अब बहुत जरूरी हो गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बार–बार आजादी के 100 वर्ष पूरे होने यानी 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का दावा कर रही है तो क्या एक विकसित भारत में भी हमारा देश अतीत की गठरी लेकर ही प्रवेश करेगा? इस सवाल का जवाब अब तो ढूंढ ही लेना चाहिए।

यूजीसी : पिछड़े दलितों का नेतृत्व पूरी तरह असफल

नीरज

दलित पिछड़ों को क्या मिला? मंडल के 35 साल बाद फिर वैसा ही सवर्ण आंदोलन हुआ और इस बार उन्होंने जीत भी हासिल कर ली। मंडल के समय प्रधानमंत्री वीपी सिंह की वजह से नहीं।मंडल क्यों आया था इसके बहुत सारे कारण हैं। मगर पिछड़ों के किसी आंदोलन की वजह से नहीं। वह पिछड़ों को आसमान से टपका लाभ था। उसका बाद पिछड़ों के नेताओं को सत्ता लाभ भी मिला।

का राजनीतिक अस्तित्व दांव पर लगा था इसलिए मंडल लागू हो गया। मगर इस बार सरकार समानता के साथ नहीं थी इसलिए असमानता का पुराना जमाना बरकरार रहा। देश के कमजोर वर्ग के पास अगर नेतृत्व होता तो यूजीसी के समानता नियम इस तरह ठंडे बस्ते में नहीं जा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार पर अगर दबाव पड़ता तो उसे कानून बनाकर समानता के इन नियमों को बनाए रखना पड़ता। नियम दलित पिछड़े आदिवासी छात्र–छात्राओं को विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में जातिगत भेदभाव से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बनाए गए थे। किसी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार को और उत्तर प्रदेश में मुलायम, अखिलेश यादव को। दलित उभार भी हुआ और इसकी वजह से मायावती मुख्यमंत्री बनीं और रामविलास पासवान बड़े नेता। शरद यादव भी बड़े नेता बने। मगर दलित पिछड़ों को क्या मिला? मंडल के 35 साल बाद फिर वैसा ही सवर्ण आंदोलन हुआ और इस बार उन्होंने जीत भी हासिल कर ली। मंडल के समय प्रधानमंत्री वीपी सिंह का राजनीतिक अस्तित्व दांव पर लगा था इसलिए मंडल लागू हो गया। मगर इस बार सरकार समानता के साथ नहीं थी इसलिए असमानता का पुराना जमाना बरकरार रहा। जिसकी वजह से रोहित वेमूला, पायल तड़वी और कई वो जो चर्चा में नहीं आ पाए जिन्दा नहीं बचे।समानता नियम में क्या था? कि प्रशासन को सुनवाई करना पड़ेगी। रोहित वेमूला और पायल तड़वी का परिवार यही कहने तो सुप्रीम कोर्ट में गया था उनके बच्चों पर अन्याय होता रहा मगर शिक्षण संस्थाओं ने उनकी नहीं सुनी। अब और ज्यादा नहीं सुनेंगे! सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगाकर उन तत्वों को और ज्यादा हिम्मत दे दी है जो जातिगत आधार पर भेदभाव करते हैं और यह मानते हैं कि दलित आदिवासी पिछड़ों को उतनी शिक्षा का अधिकार नहीं है जितनी हमने प्राप्त की है और हमारे बच्चे कर रहे हैं। अगर कोई सोशल मीडिया पर स्टडी करके पिछले दो हफ्ते के कमेंट निकाले तो मालूम पड़ जाएगा कि वंचित समुदाय के लिए क्या क्या कहा गया है।कौन करेगा यह काम? यहीं नेतृत्व की जरूरत मालूम पड़ती है। सवर्णों की तरफ से बताया जाने लगा कि एससी एसटी एक्ट का कितना दुरुपयोग हुआ है। सच झूठ किसी को नहीं मालूम मगर ह्वाट्सएप ग्रुपों से लेकर मीडिया तक में पहले से बनाई गई धारणा को बढ़ावा दिया जाने लगा कि नए नियमों का भी ऐसे ही दुरुपयोग होगा और ठीक यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। दुरुपयोग की आशंका। हमने पहले भी बताया है फिर बता रहे हैं कि ऐसे ही अंग्रेज कहते थे कि भारत में आजादी के दुरुपयोग की आशंका होगी। खुद वहां के प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल ने कहा था।दलित पिछड़े आदिवासी इसका जवाब कैसे देंगे? पहली बात तो खुद जागरुक नहीं है और फिर यही सवाल कि जागरुकता, चेतना आती कैसे है? जनशिक्षण से। और यह कौन करता है नेतृत्व। नेहरु अपने कैबिनेट के मंत्रियों को सैद्धांतिक क्लासों में भेजते थे। सिद्धांत मजबूत होना चाहिए। दलितों में आम्बेडकर के बाद कोई जनशिक्षण करने वाला नहीं हुआ। कांशीराम ने अपने शुरुआती दौर में यह काम किया। मगर बाद में सिर्फ मायावती को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी सारी ताकत लगाए रखे और मायावती उन्होंने तो दलित चेतना आगे बढ़ाने के बदले नए नियमों को समाज में तनाव बढ़ाने वाला बता दिया। वे संघ और भाजपा जितनी ही प्रतिगामी होने की कोशिश कर रही हैं। दलितों में क्या नया नेतृत्व पैदा होगा? अन्य पिछड़ों के लिए यह सवाल और ज्यादा जरूरी है। यूजीसी के नए नियमों में पीड़ितों में पिछड़ों को भी जोड़ा गया था। इससे पहले एससी एसटी एक्ट ही काम करता था। उसमें पिछड़े नहीं थे। मायावती जो नए नियमों को समाज में तनाव पैदा करने वाला बता रही हैं उसका बड़ा कारण पिछड़ों का इन नए नियमों में आना है। बचाव पिछड़ें पर छोड़ दिया गया। मगर पिछड़ों के पास तो इस तरह का नेतृत्व बिल्कुल ही नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों में स्वाभिमान जगाने का काम किया। मगर वह सब पिछड़ों के लिए नहीं हो सका। उनकी जाति के लोगों को ही इसका ज्यादा फायदा मिला। व्यापक पिछड़ा हित जैसा काम नहीं हो सका। फिर जनशिक्षण के अभाव में दूसरी पिछड़ी जातियों और यादवों के बीच दूरी बढ़ती चली गई। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में हुआ। मायावती की जाति में जो चेतना आई वह दूसरी दलित जातियों में पैदा करने की कोशिश ही नहीं हुई। जाहिर है कि उनकी अपनी जाति का नेतृत्व इतना काम नहीं कर पाया। नीतीश ने पिछड़ों और दलितों की एकता को महादलित और अति पिछड़ा बनाकर और तोड़ डाला। यह लोग यह नहीं देखते हैं कि अभी नए नियमों के विरोध में सारे सवर्ण बिना अपने जातिगत भेदभाव के एक साथ आए। जीते। यहां तो कमजोर वर्ग में पहले दलित और पिछड़ों में ही भारी मतभेद है। उत्तर प्रदेश में मायावती किसी भी कीमत पर अखिलेश के साथ लड़ने को तैयार नहीं हैं। भाजपा के साथ चली जाती हैं। अभी उसी की राजनीति की मदद कर रही हैं। सरकारी नौकरी निकाल नहीं रहे हैं। तो आरक्षण खत्म हो रहा है। जो नौकरियां हैं वहां नॉट फाउन्ड सुटेबल (एनएफएस) के नाम पर आरक्षित सीटें भरी नहीं जाती हैं। दलित आदिवासी पिछड़ों के नेताओं को मालूम है कि संसद में पिछले साल सरकार ने बताया था कि ... साल से कोई नई भर्ती नहीं की गई है? अभी संसद चल रही है। बजट सत्र है। रोज जा रहे हैं। जरा मालूम कर के देखें कि कोई भर्ती हुई है? सब ठेके के लोगों से काम चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम जनता का पैसा बचा रहे हैं। यहां लोग बेमतलब में आकर बहस करें इसलिए बता देते हैं कि पिछले महीने ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों से यह कहा। अपनी सोच के अनुरूप गढ़े हुए तर्क। सुप्रीम कोर्ट का तर्क भी ऐसा ही है दुरुपयोग की आशंका। यहां नौकरी न देना जनता का पैसा बचाना। मगर समस्या वही है। कमजोर वर्ग दलित पिछड़े आदिवासी जनता में जागरुकता का अभाव। और उनका राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक नेतृत्व कहीं दिखता नहीं। केवल सांसद विधायक मुख्यमंत्री मंत्री बनना नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व का मतलब नेहरू जैसा। जो लगातार प्रगतिशीलता, वैज्ञानिक चेतना फैलाते रहते थे। और सब को साथ लेकर चलते थे। यहां लिखे के अनुसार सब का नेतृत्व करते थे। गरीब कमजोर का खासतौर से। मंडल ने पिछड़ों को कुछ लाभ तो दिया। मगर जाति भी उसी से ऊपर उठकर की जाने वाली राजनीति को मंडल और उसी के साथ बाबरी मस्जिद शहादत ने भारी धक्का पहुंचाया। पिछड़े दलितों के नेता अलग हो गए। मुस्लिम में भी क्षेत्रीय दलों के साथ जाने से लेकर अपनी कयादत (नेतृत्व) के नाम पर ओवैसी के साथ जाने का सिलसिला शुरू हो गया। मगर जो पूरे समाज को साथ लेकर चले वह नेतृत्व कमजोर हो गया। भारत में इतनी विविधता है कि कुछ मुद्दों पर अपना नेतृत्व जरूरी हो सकता है। मगर रोजमर्रा की जिन्दगी, समस्याओं के लिए जाति धर्म से ऊपर उठा नेतृत्व ही हर वर्ग के लिए और देश समाज के लिए कारामद है।

जी राम जी अधिनियम और लचीली एवं सतत् आजीविकाओं की दिशा में भारत की यात्रा

डॉ. विभा धवन

पिछले लगभग दो दशकों से ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम भारत की सामाजिक सुरक्षा संरचना का केंद्रीय स्तंभ रहे हैं। वर्ष 2005 में अधिनियमित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) ने ग्रामीण परिवारों को आय सुरक्षा प्रदान की है, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार किया है तथा आवश्यक सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन में योगदान दिया है। जैसे–जैसे ग्रामीण भारत तीव्र आर्थिक, प्रौद्योगिक और पर्यावरणीय परिवर्तनों से गुजर रहा है, उभरती चुनौतियों और अवसरों का प्रभावी ढंग से उत्तर देने के लिए इस ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने की तात्कालिक आवश्यकता है। विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 इस क्रमिक विकास को प्रतिबिंबित करता है। ग्रामीण रोजगार गारंटी ढांचे में सुधार के माध्यम से यह अधिनियम इस तथ्य को मान्यता देता है कि सतत् ग्रामीण समृद्धि केवल रोजगार सृजन पर ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जलवायु जोखिमों के प्रति लचीलेपन तथा आजीविकाओं की संवेदनशीलता के संरक्षण पर भी आधारित होनी चाहिए। यह समेकित दृष्टिकोण ऐसे समय में अत्यंत प्रासंगिक है, जब ग्रामीण समुदाय जलवायु परिवर्तनशीलता, चरम मौसमीय घटनाओं और संसाधन दबाव के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता का सामना कर रहे हैं। जी राम जी अधिनियम क्यों विशिष्ट है जी राम जी अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें मजदूरी आधारित रोजगार को चार प्राथमिक क्षेत्रों के साथ संरेखित करने पर विशेष बल दिया गया हैरूजल सुरक्षा, मूल ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका से संबंधित अवसंरचना तथा चरम मौसमीय घटनाओं के शमन से जुड़े कार्य। यह ग्रामीण रोजगार नीति के पर्यावरणीय और लचीलापन संबंधी आयामों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जल से संबंधित कार्य, मृदा एवं भूमि संरक्षण, जल निकासी प्रणालियों तथा जलवायु–अनुकूल अवसंरचना कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के साथ–साथ बाढ़, सूखा और भूमि क्षरण के प्रति संवेदनशीलता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब ऐसी परिसंपत्तियों को प्रभावी ढंग से नियोजित तथा कार्यान्वित की जाती हैं, तो वे कई लाभ उत्पन्न करती हैंरूअल्पकालिक रोजगार सृजन, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन तथा दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा। इन क्षेत्रों पर अधिनियम का विशेष बल इस तथ्य को रेखांकित करता है कि रोजगार कार्यक्रम एक साथ सामाजिक संरक्षण और जलवायु अनुकूलन के प्रभावी साधन के रूप में कार्य कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर लचीलापन अधिनियम की नियोजन पारिस्थितिकीरूजिसका केंद्र विकसित ग्राम पंचायत योजनाएँ हैं तथा जिसमें परिसंपत्तियों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के अंतर्गत एकीकृत किया गया हैरूग्रामीण विकास के लिए एक सुसंगत और भविष्य के लिए तैयार दृष्टिकोण का समर्थन प्रदान करती है। विकेन्द्रीकृत नियोजन के माध्यम से पंचायतों को स्थानीय प्राथमिकताओं की पहचान करने का अवसर मिलता है, जबकि राष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण व्यापक अवसंरचना एवं विकास उद्देश्यों के साथ समन्वय सुनिश्चित करता है। कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से यह ढांचा रोजगार गारंटी के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, स्थायित्व और प्रासंगिकता में सुधार का अवसर प्रदान करता है। पर्याप्त तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से पंचायती राज संस्थान यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि सार्वजनिक कार्य, संसाधन संरक्षण तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सार्थक योगदान दें। अधिनियम के अंतर्गत परिकल्पित पारदर्शिता तंत्र, डिजिटल निगरानी उपकरण और सामाजिक अंकेक्षण जवाबदेही को और सुदृढ़ करते हैं तथा सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करते हैं। सामाजिक संरक्षण और लचीलेपन पर ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) सतत् विकास के प्रति वचनबद्ध एक शोध संस्थान के रूप में, टेरी ने यह समझने के लिए व्यापक रूप से कार्य किया है कि ग्रामीण समुदायों में लचीलापन विकसित करने के लिए सामाजिक संरक्षण तंत्रों को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है। हमारे शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि जब रोजगार कार्यक्रमों को पर्यावरणीय योजना और जोखिम–सूचित रूपरेखा के साथ जोड़ा जाता है, तो वे घरेलू तथा सामुदायिकरूदोनों स्तरों पर अनुकूलन क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकते हैं। टेरी ने जलवायु लचीलापन, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन तथा आजीविका की निरन्तरता को सम्मिलित करने हेतु नीतिगत ढांचों के पुनरोद्धार और सुदृढ़ीकरण से संबंधित सरकारी प्रक्रियाओं में विश्लेषणात्मक योगदान प्रदान किया है। इसमें कार्यक्रम अभिकल्पना में लचीलापन संबंधी पहलुओं के एकीकरण को समर्थन देना तथा रोजगार सृजन के साथ–साथ दीर्घकालिक पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों को प्रतिबिंबित करने वाले संकेतकों की पहचान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, टेरी ने ऐसे वित्तीय मॉडल और नियोजन दृष्टिकोणों का अध्ययन किया है।

खाद्य पदार्थो मे मिलावट करने वाले होटल, रेस्टोरेंट पर विभाग द्वारा चलाया जायेगा चेकिंग अभियान - मानिक चंद्र

अयोध्या। शहर मे इस समय कई जगहों पर स्थित होटल व रेस्टोरेंट पर ग्राहकों को खुले रुप से संक्रमण खाद्य पदार्थ परोसा जा रहा है।इसके अलावा कुछ ठेलो व मिठाइयों की अन्य दुकानों पर सड़े गले खाद्य पदार्थ भी बिकने की शिकायत खाद्य प्रशासन को मिल रही है।बताते चलें कि इधर काफी दिनों से अयोध्या धाम के अन्य प्रमुख स्थान पर स्थित कई ऐसे रेस्टोरेंट तथा होटल के अलावा ठेलो पर बिकने वाले खाद्य पदार्थ में मिलावट की शिकायत आ रही है।अभी इसको लेकर भी एक दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था।मालूम हो कि शहर के रिकाबगंज, सिविल लाइन,देवकाली, चौक, रीडगंज, बेनीगंज, रोडवेज, नियावा, गुदडीबाजार, वजीरगंज, फतेहगंज के अलावा कई जगहों पर संक्रमण युक्त खाद्य पदार्थ ग्राहकों व बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है।यही हाल अयोध्या धाम की है जहां पर कई ऐसे होटल रेस्टोरेंट है जहां पर सडे गले खाद्य पदार्थों को परोसकर उनके सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है।परंतु इस गंभीर समस्या पर इससे संबंधित विभाग चुप्पी साधे रहता है हां इतना जरूर है जब दीपावली रक्षाबंधन होली सहित अन्य प्रमुख पर्व आते हैं तब खाद्य विभाग कुंभकर्णी नीति से जाकर जिले के कुछ छोटे–मोटे प्रतिष्ठानों पर छापा डालकर वह वही लूट लेते हैं। जबकि देखा जाए की रामनगरी में श्रद्धालुओं के अलावा अन्य लोग बीच–बीच में प्रमुख पर्वों पर आते हैं और इसका लाभ उठाकर यहां पर स्थित होटल तथा रेस्टोरेंट के स्वामी संक्रमण युक्त खाद्य पदार्थों को देकर उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं।इस संबंध में सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मानिकचंद ने बताया की बीच–बीच में मिलावट और लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले होटल रेस्टोरेंटों पर कार्यवाही की जाती है हां इतना जरूर है इधर कुछ दिन से कार्यवाही नहीं की गई है जिसमें हमारे विभाग के अधिकतर कर्मचारियों की ड्यूटी एसआईआर में लगी हुई है।कुछ निरीक्षक व अन्य कर्मी अन्य काम से गए हैं लेकिन एक या दो दिन में टीम का गठन कर ग्राहकों के सेहत से खिलवाड़ करने वाले होटल रेस्टोरेंट पर छापामारी का अभियान चलाया जाएगा।उन्होंने इस तरह के म करने वाले होटल तथा रेस्टोरेंटों के स्वामियों तथा कर्मचारियों से चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि वह अपने प्रतिष्ठान के पैंट्री रूम को साफ सुथरा रखे, खाद्य विभाग द्वारा तय किए गए मानक पर खड़े उतरे नहीं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

महिला की गला दबाकर हत्या, बदमाश ने हाथों के कड़े और कान के झुमके लूटे

लखनऊ, (संवाददाता)। बाराबंकी में शहर कोतवाली क्षेत्र के बंकी कस्बा निवासी अशोक कुमार शुक्ला भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में कार्यरत हैं। उनके परिवार में 80 वर्षीय माता शकुंतला शुक्ला, पत्नी और दो अविवाहित बेटे शामिल हैं। परिवार का तीन मंजिला मकान कस्बे में स्थित है। रविवार रात शकुंतला शुक्ला मकान के निचले हिस्से में अपने कमरे में सो रही थीं, जबकि परिवार के अन्य सदस्य ऊपर के मंजिलों पर थे। इसी दौरान बदमाश गली की ओर खुलने वाले दूसरे दरवाजे से मकान में दाखिल हुए। परिजनों के अनुसार बदमाशों ने शकुंतला शुक्ला का गला दबाकर हत्या कर दी और उनके हाथों में पहने सोने के कड़े, कानों के झुमके व गले के अन्य जेवरात लूटकर फरार हो गए। सोमवार सुबह करीब 9रू30 बजे जब परिवार नीचे पहुंचा तो घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। परिजनों ने बताया कि इसी परिवार के यहां एक माह पूर्व करीब 85 हजार रुपये की चोरी की घटना भी हो चुकी है। शहर कोतवाल सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

संक्षिप्त खबरें

चार उप निरीक्षक पदोन्नति पाकर बने निरीक्षक

अयोध्या।जिले में तैनात चार उप निरीक्षकों की पदोन्नति निरीक्षक पद पर हुई है।जिसमें से कोतवाली नगर में तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक प्रदीप कुमार के साथ –साथ रिकाबगंज चौकी प्रभारी के रूप में तैनात उपनिरीक्षक रघुवीर सिंह की पदोन्नति निरीक्षक पद पर हुई है।वहीं इनके अलावा जिले में तैनात दो अन्य उप निरीक्षक महेंद्र कुमार तथा वीरेंद्र कुमार राय की भी पदोन्नति उप निरीक्षक पद से निरीक्षक पद पर हुई है।बताते चलें कि इन पुलिस कर्मियों के पदोन्नति की सूचना मिलने पर पुलिस विभाग के आला अधिकारियों व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अश्वनी पांडे के अलावा अन्य पुलिस कर्मियों ने उन्हें शुभकामना दिया।इसके अलावा पदोन्नति पाये पुलिस कर्मियों के शुभचिंतकों ने भी उन्हें बधाई दिया।

होटल वाले रेस्टोरेंट पर परोसा जा रहा है लोगों को संक्रमण युक्त खाद्य पदार्थ

अयोध्या।शहर मे इस समय कई जगहों पर स्थित होटल व रेस्टोरेंट पर ग्राहकों को खुले रुप से संक्रमण खाद्य पदार्थ परोसा जा रहा है।इसके अलावा कुछ ठेलो व मिठाइयों की अन्य दुकानों पर सड़े गले खाद्य पदार्थ भी बिकने की शिकायत खाद्य प्रशासन को मिल रही है।बताते चलें कि इधर काफी दिनों से अयोध्या धाम के अन्य प्रमुख स्थान पर स्थित कई ऐसे रेस्टोरेंट तथा होटल के अलावा ठेलो पर बिकने वाले खाद्य पदार्थ में मिलावट की शिकायत आ रही है।अभी इसको लेकर भी एक दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था।मालूम हो कि शहर के रिकाबगंज, सिविल लाइन,देवकाली, चौक, रीडगंज, बेनीगंज, रोडवेज, नियावा, गुदडीबाजार,वजीरगंज,फतेहगंज के अलावा कई जगहों पर संक्रमण युक्त खाद्य पदार्थ ग्राहकों व बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है।यही हाल अयोध्या धाम की है जहां पर कई ऐसे होटल रेस्टोरेंट है जहां पर सडे गले खाद्य पदार्थों को परोसकर उनके सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है।परंतु इस गंभीर समस्या पर इससे संबंधित विभाग चुप्पी साधे रहता है हां इतना जरूर है जब दीपावली रक्षाबंधन होली सहित अन्य प्रमुख पर्व आते हैं तब खाद्य विभाग कुंभकर्णी नीति से जाकर जिले के कुछ छोटे–मोटे प्रतिष्ठानों पर छापा डालकर वह वही लूट लेते हैं। जबकि देखा जाए की रामनगरी में श्रद्धालुओं के अलावा अन्य लोग बीच–बीच में प्रमुख पर्वों पर आते हैं और इसका लाभ उठाकर यहां पर स्थित होटल तथा रेस्टोरेंट के स्वामी संक्रमण युक्त खाद्य पदार्थों को देकर उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं।इस संबंध में सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मानिकचंद ने बताया की बीच–बीच में मिलावट और लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले होटल रेस्टोरेंटों पर कार्यवाही की जाती है हां इतना जरूर है इधर कुछ दिन से कार्यवाही नहीं की गई है जिसमें हमारे विभाग के अधिकतर कर्मचारियों की ड्यूटी एसआईआर में लगी हुई है।कुछ निरीक्षक व अन्य कर्मी अन्य काम से गए हैं ।

कायस्थ समाज के लिए समर्पित है कायस्थ महासभा 7235 भारत : सत्य प्रकाश श्रीवास्तव

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। बंगाल से शुरू हुआ कायस्थ महासभा 7235 भारत आज देश स्तर पर मजबूती से कार्य कर रहा हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में तेजी से पूरे देश में विस्तार हो रहा है उक्त विचार कायस्थ महासभा 7235 भारत के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सत्य प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट हाईकोर्ट मुंबई ने आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर दौरे पर आए कायस्थ महासभा 7235 के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस जौनपुर के जिला अध्यक्ष डॉ उमाकांत श्रीवास्तव प्रिंसिपल साहब के उमरपुर आवास पर अपने स्वागत अभिनंदन समारोह में कहा कि कायस्थ समाज जौनपुर का नाम देश भर में चर्चा में रहता है और लोग आपसी एकजुटता का मिसाल देते है। सत्य प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है अभी महाराष्ट्र में प्रदेश कार्यसमिति बैठक मुंबई में हुआ था जिसमें कायस्थ समाज ने भारी संख्या में शामिल हो कर कायस्थ महासभा 7235 से जुड़कर संगठन को मजबूत बनाए बैठक में सांसद संजय निरुपम जी सहित अनेक जनप्रतिनिधि मंत्री अधिकारी ने मार्गदर्शन दिया और मुंबई में भगवान चित्रगुप्त जी मंदिर निर्माण हेतु साथ देने का वादा किया। और कहा कि कायस्थ समाज ने देश के आजादी से लेकर आज तक राष्ट्रहित में कार्य कर रहा है और करता रहेगा। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव साधु ने कहा कि कायस्थ महासभा 7235 भारत संगठन कायस्थ समाज को जोड़ने एवं जागरूक करने का कार्य करता है और जौनपुर में एक नई पीढ़ी युवाओं की फौज खड़ी हो गई हैं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चन्द श्रीवास्तव दीनू जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कायस्थ महासभा 7235 संगठन मजबूत किया जा रहा है शीघ्र ही लखनऊ में एक प्रदेश कार्यसमिति बैठक एवं कायस्थ सम्मलेन आयोजित किया जाएगा जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के कायस्थ समाज के लोग शामिल होंगे और कहा कि शीघ्र ही लखनऊ में एक प्रदेश कार्यालय खोला जाएगा।

टैरिफ से जूझती लेदर इंडस्ट्री को कस्टम नियमों और विदेशी निवेश में राहत

लखनऊ, (संवाददाता)। अमेरिकी टैरिफ की चुनौतियों के बीच केंद्रीय बजट ने लेदर इंडस्ट्री को आंशिक राहत दी है। उद्योग का मानना है कि एमएसएमई, कस्टम नियमों में सरलीकरण, डिजाइन और विदेशी निवेश से जुड़े फैसलों से यूपी के लेदर सेक्टर को मजबूती मिलेगी, हालांकि कुछ अहम मांगें अब भी लंबित हैं। अनुमान है कि इन प्रावधानों से अगले तीन साल में यूपी के लेदर बाजार में करीब 5000 करोड़ रुपये का उछाल आएगा और लगभग 3000 करोड़ रुपये का नया विदेशी निवेश आएगा। लेदर इंडस्ट्री के मुताबिक बजट में हर सेक्टर को टच किया गया है। लेदर सेक्टर की 95:98 फीसदी इकाइयां एमएसएमई के तहत आती हैं। बजट में ट्रेड स्कीम का सरलीकरण और 10 हजार करोड़ रुपये से एमएसएमई चौंपियन बनाने की पहल को उद्योग के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। इससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी बेहतर लाभ मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना से घरेलू डिजाइन क्षमता बढ़ेगी और युवाओं को अवसर मिलेंगे। फेमा में संशोधन के बाद फुटवियर सेक्टर में सीधा विदेशी निवेश आने का रास्ता साफ होगा। क्रस्ट और फिनिश्ड लेदर पर ड्यूटी खत्म करने की उम्मीद पूरी नहीं हुई, हालांकि दरों में कुछ कमी की गई है। कस्टम एक्ट के सरलीकरण से अब निर्यात के लिए पैक माल नहीं खोला जाएगा। एआई स्कैनर से जांच होगी। फैक्टरी–सील कंटेनर सीधे पोर्ट तक जाएंगे, जिससे करीब तीन दिन की बचत और ट्रांजेक्शन लागत में कमी आएगी। कोरियर में अनलिमिटेड वैल्यू की छूट से निर्यात ऑर्डर में 20 फीसदी तक बढ़ोतरी की संभावना है। एफडीडीआई के अध्यक्ष व चर्म निर्यात परिषद के पूर्व अध्यक्ष आर के जालान ने कहा कि इंडस्ट्री की कई मांगें मानी गई हैं। लेदर सेक्टर को फायदा होगा। फुटवियर अपर का आयात की अनुमति नहीं थी। इसे भी मंजूरी मिल गई। ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट की समयसीमा एक साल होना बड़ी राहत है। ग्रोथ 10:12 फीसदी रहने की उम्मीद है।

संक्षिप्त खबरें

हिंदू एकजुट होकर एक मंच पर आएं

लखनऊ, (संवाददाता)। शहर के अलग–अलग इलाकों में रविवार को हिंदू सम्मेलन हुआ। श्रीहनुमान सेतु मंदिर परिक्षेत्र में विराट हिंदू सम्मेलन हुआ। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र संपर्क प्रमुख मनोज रहे। मुख्य अतिथि लविवि कुलपति प्रो. जेपी सैनी, बलरामपुर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. देवाशीष शुक्ल एवं पूज्य आचार्य कौशिक चौतन्य ब्रह्मचारी उपस्थित रहे। मनोज ने कहा कि समस्त हिंदू समाज जब एक होगा तभी एकता के सूत्र का मंत्र सिद्ध होगा। कार्यक्रम में आलोक, विशाल शुक्ल, प्रो. राकेश द्विवेदी, डॉ. रमेश त्रिपाठी, डॉ. राजेश्वर यादव, डॉ. महेंद्र अग्निहोत्री सहित 1500 से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संचालन सात्विक मिश्र ने किया। सकल हिंदू समाज की ओर से गोमतीनगर विराटखंड स्थित स्कूल में हिंदू सम्मेलन हुआ। इसमें मुख्य वक्ता डॉ. अनिल मिश्रा ने कहा कि हिंदू समाज एक मंच पर आए। ऊंच–नीच का भेद मिटाए तभी संघ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। पर्यावरण स्वच्छ रहे इसके लिए हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए। कार्यक्रम में ज्योति, बांके श्याम त्रिपाठी, ज्योति प्रकाश, डॉ. माता प्रसाद समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में मजबूत कदम है केंद्रीय बजट

लखनऊ, (संवाददाता)। गोमतीनगर के विकासखंड स्थित आईसीएआई भवन में रविवार को केंद्रीय बजट पर चर्चा हुई। लखनऊ शाखा ऑफ आईसीएआई के अध्यक्ष सीए अनुराग पांडेय ने कहा कि केंद्रीय बजट दूरदर्शी और विकासपरक बजट है। भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में एक और मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में हर क्षेत्र को विकास की रफ्तार दी गई है। सबका साथ और सबका विकास को ध्यान में रखते हुए उत्पादन, तकनीक, पर्यटन, खनिज, ब्याज और आयकर में छूट देकर हर वर्ग तक लाभ पहुंचाया गया है। बजट में स्वास्थ्य, खेल, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दिया गया है। इस दौरान प्रबंध समिति के सदस्य अंशुल अग्रवाल के अलावा लखनऊ और आसपास के शहरों के कई सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया।

कैंसर से डरे नहीं बल्कि डटकर किया मुकाबला

लखनऊ, (संवाददाता)। एलडीए कॉलोनी के रहने वाले विलियम इरफान को बीते साल जीभ में एक छाला निकल आया। जो धीरे–धीरे बढ़ा होने लगा। निजी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जांच कराई तो कैंसर की पुष्टि हुई। उन्होंने ऑपरेशन कराकर पूरा इलाज कराया। इस दौरान वह तनिक भी घबराएं नहीं। मरीज के साहस के आगे बीमारी ने घुटने टेक दिए। कैंसर सर्वाइवर ने रविवार को कानपुर रोड स्थित कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के जरिये किए गए उमंग सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा किया। कार्यक्रम के तहत 150 से अधिक कैंसर सर्वाइवर, उनके पारिवारिक सदस्य, डॉक्टर, देखभाल करने वाले और खास मेहमान शामिल हुए। कार्यक्रम में पांच कैंसर सर्वाइवर ने अपने इलाज और ठीक होने के सफर को सबके बीच साझा किया।

यूपी में पूरब से पश्चिम तक बढ़ेगा सांस्कृतिक पर्यटन का दायरा, सृजित होंगे रोजगार के नए अवसर

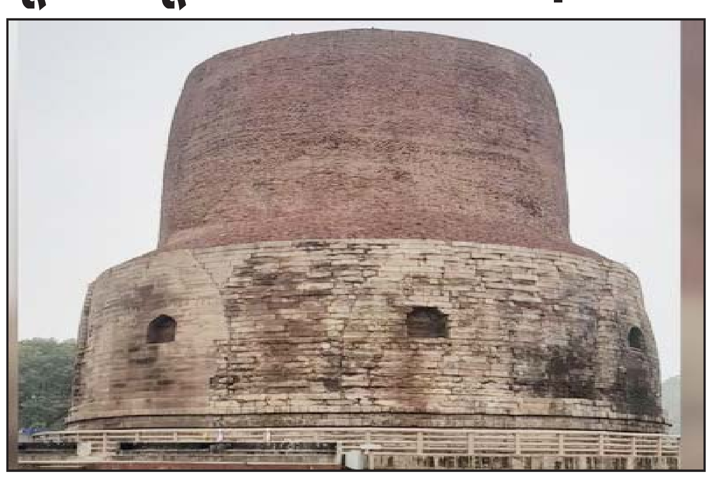

लखनऊ, (संवाददाता)। केंद्रीय बजट ने यूपी के सांस्कृतिक पर्यटन को नई पहचान देने की पहल की है। पूरब में सारनाथ (वाराणसी) से लेकर पश्चिम में हस्तिनापुर (मेरठ) तक, प्रदेश के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों को विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। देश के 15 पुरातात्विक महत्व के स्थलों के विकास, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और गाइड के रूप में 10 हजार युवाओं के कौशल विकास के जरिये जहां पर्यटन अनुभव समृद्ध होगा। वहीं यूपी के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। हालांकि, बौद्ध सर्किट जैसी अहम योजनाओं से यूपी का बाहर रहना मायूस करने वाला रहा। बजट में आध्यात्मिक और विरासत से जुड़े सभी स्थलों की राष्ट्रीय स्तर पर मैपिंग और दस्तावेजीकरण की घोषणा से सारनाथ के स्तूपों व हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों के वैभव, राजसी संघर्षों व गाथाओं आदि से जुड़ी चीजों का बेहतर संरक्षण होगा। डिजिटल तकनीक के प्रयोग से देश–विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी। यहां व्याख्यान केंद्र व गाइड की सहायता से पर्यटकों को इससे जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। यहां विश्वस्तरीय पर्यटक सुविधाएं, क्यूरेटेड वॉकवे, इंटरपटेशन सेंटर व तकनीक आधारित स्टोरी टेलिंग की सुविधाएं होंगी। इससे पर्यटक सारनाथ व हस्तिनापुर के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को आसानी से समझ सकेंगे। बजट में होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए नए प्रशिक्षण और मानक तय करने की घोषणा की गई है। देश भर के 20 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइड को 12 हफ्तों का हाइब्रिड कोर्स का प्रशिक्षण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) के सहयोग से दिलाया जाएगा। यह योजना भी प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगी। अयोध्या, वाराणसी समेत कुछ स्थलों पर ट्रायल के रूप में युवाओं को गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ा गया है। यही नहीं पर्यटन विभाग नाविकों, ई रिक्शा व ऑटो चालकों आदि को भी प्रशिक्षण दे रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ यूपी को और बेहतर करने में मिलेगा। इससे पर्यटकों को और बेहतर जानकारी व सुविधाएं मिल सकेंगी। राज्य सरकार ने अपने यहां ऐतिहासिक महत्व के स्थलों से जुड़ी पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण कराने की शुरुआत की है। केंद्रीय बजट में सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कर स्थानीय शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और कंटेंट क्रिएटरों के लिए भी रोजगार सृजित किए जाने की घोषणा की गई है। इसका भी लाभ यूपी को मिलेगा। छोटे शहरों में तीर्थ स्थल विकसित करने की योजना पर यूपी में पहले से काम चल रहा है। ऐसे में केंद्र का सहयोग इसे गति देगा। बुद्धिस्ट सर्किट में खाली हाथ रहा यूपी केंद्रीय बजट में बौद्ध पर्यटन स्थलों के विकास के लिए पूर्वोदय योजना की घोषणा की गई है। इसमें पूर्वोत्तर के पांच राज्यों अरुणाचल, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा। इस मामले में यूपी के हिस्से कुछ नहीं आया। प्रदेश में बौद्ध सर्किट में सारनाथ, कुशीनगर, संकिसा, कौशाम्बी आदि शामिल हैं। यहां विकास की काफी संभावनाएं हैं। इसके लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को पूर्व में प्रस्ताव भी भेजा गया था लेकिन केंद्रीय बजट में कुछ नहीं मिला। वाइल्डलाइफ पर्यटन में ओडिशा, कर्नाटक और केरल में कछुआ ट्रेल्स और पुलिकट झील के आसपास बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स बनाई जाएंगी, किंतु इसमें यूपी के हिस्से कुछ नहीं आया।

बजट में व्यापारियों के लिए कोई प्रावधान न होने पर जताया असंतोष

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने हजरतगंज स्थित एक होटल में बजट पर हुई चर्चा में व्यापारियों के लिए कोई प्रावधान न होने पर असंतोष जाहिर किया। संगठन के मुखिया संजय गुप्ता ने केंद्रीय बजट को शुष्क बजट बताते हुए कहा कि आम जनता व व्यापारियों को कुछ नहीं मिला। चिकित्सा, शिक्षा, युवा, महिला पर भी ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। संजय गुप्ता ने कहा वित्तमंत्री ने परंपरागत व्यापारियों की इस बजट में कोई चर्चा नहीं की और न ही व्यापारियों को कुछ दिया, जबकि विदेशी ई–कॉमर्स कंपनियों के कारण देश का परंपरागत व्यापारी बहुत परेशान है। ई कॉमर्स पॉलिसी एवं रिटेल ट्रेड पॉलिसी की सख्त आवश्यकता है, लेकिन वित्त मंत्री ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। उत्तर प्रदेश की भी चिंता बजट में नहीं की गई। दक्षिण के राज्यों और समुद्र तट पर स्थित राज्यों पर पूरा फोकस किया गया। उन्होंने व्यापारियों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य व जीवन बीमा देने की मांग की। नगर अध्यक्ष हरजिंदर सिंह ने कहा कि व्यापारियों को भी स्वास्थ्य बीमा मिलना चाहिए था। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अविनाश त्रिपाठी, प्रदेश कोषाध्यक्ष मो. अफजल, प्रदेश मंत्री संदीप सिंह गौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह चड्ढा, ट्रांसगोमती प्रभारी मनीष पांडेय, ट्रांस गोमती अध्यक्ष अनिरुद्ध निगम, महिला इकाई की उपाध्यक्ष वर्तिका शुक्ला ट्रांस गोमती अध्यक्ष अंजलि मोर्य, रितु सिंह, मीनू सक्सेना आदि मौजूद रहीं।

कौशल और उद्यमिता को केंद्र में रखकर विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को सशक्त आधार देने वाला केंद्रीय बजट 2026दृ27 देश के लिए ऐतिहासिक और दूरदर्शी है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत नौवें बजट को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के अनुरूप विकसित राष्ट्र की दिशा में मील का पत्थर बताया।मंत्री अग्रवाल ने कहा कि यह बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने, निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व स्थापित करने और युवाओं, किसानों, श्रमिकों एवं उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। बजट में युवाओं को रोजगार, किसानों को सम्मान और एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे देश की औद्योगिक क्षमता में नई गति आएगी।उन्होंने बताया कि 5 लाख तक की आबादी वाले शहरों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की घोषणा सराहनीय है, जिससे उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों सहित मुजफ्फरनगर को भी लाभ मिलेगा। घरेलू उपयोग की आवश्यक वस्तुओं को सस्ता करना, कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करना और युवाओं व किसानों के लिए नई योजनाएं प्रस्तुत करना इस बजट की विशेषता है।कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि यह बजट "युवा शक्ति–संचालित बजट" के रूप में उभरकर सामने आया है। इसमें युवाओं की आकांक्षाओं, कौशल विकास और क्षमता निर्माण को केंद्र में रखा गया है। शिक्षा से रोजगार और उद्यम तक की यात्रा को सुदृढ़ करने के लिए उच्च–शक्ति स्थायी समिति का गठन प्रस्तावित किया गया है, जो सेवा क्षेत्र को विकसित भारत का मुख्य चालक बनाने में मदद करेगी।मंत्री ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य, पशुपालन, डिजाइन, शिक्षा, पर्यटन और खेल जैसे क्षेत्रों में पेशेवर मानव संसाधन के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। इसमें एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों में अवसर सृजन, खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन और संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों व देखभालकर्ताओं के प्रशिक्षण की दिशा में स्पष्ट रोडमैप दिखाई देता है।उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए पशुपालन, उच्च मूल्य कृषि, एआई आधारित भारत–विस्टार पहल और महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए शी–मार्ट्स की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा।मंत्री अग्रवाल ने दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए कौशल आधारित योजनाओं और सहायक उपकरणों के निर्माण पर बल देने को सरकार की संवेदनशील सोच का प्रतीक बताया। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक और अनुसंधान व नवाचार को प्रोत्साहित करने वाले मिशन भारत को तकनीकी रूप से अग्रणी बनाने में सहायक होंगे।कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सशक्त विजन है।

मीडिया वर्कशॉप के साथ अयोध्या में फाइलेरिया उन्मूलन की मुहिम हुई तेज, सीएमओ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

अयोध्या (डी के यू लाइव ब्यूरो चीफ) सुरेंद्र कुमार ।अयोध्या, 3 फरवरी 2026रू राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जनपद के तारुन और मयाबजार विकासखंडों में 10 से 28 फरवरी तक सामूहिक दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा। दोनों ब्लॉकों की कुल लक्षित आबादी लगभग 4.93 लाख है। अभियान के लिए 87 सुपरवाइजर और 495 टीमें गठित की गई हैं जो घर–घर जाकर पात्र व्यक्तियों को अपने सामने दवा सेवन कराएंगी। सभी ग्राम पंचायतों में अभियान का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वयं दवा सेवन कर लोगों को प्रेरित करते हुए किया जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को सीएमओ सभागार में आयोजित मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला में सीएमओ डॉ. देवेन्द्र कुमार भिटौरिया ने दी। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया उन्मूलन की सबसे बड़ी चुनौती लोगों की फाइलेरिया से बचाव की दवा सेवन में संकोच और भ्रांतियाँ हैं। कई लोग स्वयं को स्वस्थ समझकर दवा सेवन से इनकार कर देते हैं या दुष्प्रभाव की भ्रांति से पीछे हट जाते हैं। मीडिया सही सूचना और भरोसा देकर लोगों को दवा सेवन के लिए प्रेरित कर सकता है। सीएमओ ने बताया कि फाइलेरिया केवल स्वास्थ्य समस्या नहीं बल्कि सामाजिक–आर्थिक संकट भी है। जनपद में वर्तमान में 1334 हाथीपांव और 11 हाइड्रोसील मरीज पंजीकृत हैं। यह बीमारी व्यक्ति को आजीवन कमजोर बना देती है जिससे पूरे परिवार की आजीविका प्रभावित होती है। टीम की निगरानी में खिलाई जाएगी दवा – एसीएमओ एवं बीवीडी नोडल अधिकारी डॉ. पीसी भारती ने बताया कि हालिया ब्लड सर्वे में तारुन और मयाबजार संवेदनशील पाए गए हैं। इसलिए यहां की आबादी को फाइलेरिया से बचाव के लिए 12.32 लाख डीईसी, 12.32 लाख आइवरमेक्टिन और 4.93 लाख एल्बेंडाजोल टैबलेट राज्य मुख्यालय से उपलब्ध कराई गई हैं। गर्भवती महिलाओं, दो वर्ष से छोटे बच्चों और गंभीर रोगियों को छोड़कर सभी को दवा स्वास्थ्य कर्मियों के सामने खिलाई जाएगी ताकि संक्रमण की श्रृंखला टूट सके। सुरक्षित हैं दवाएं दृसीफार के प्रतिनिधि ने बताया कि फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है, जिसके सूक्ष्म कृमि मच्छरों द्वारा दूसरों में फैलते हैं। इसके लक्षण कई वर्षों बाद हाथ–पैर या जननांगों में सूजन के रूप में दिखते हैं। इससे बचाव की दवाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और डबल्यूएचओ से प्रमाणित हैं। दवा सेवन के बाद हल्का बुखार या चक्कर आना सामान्य है ऐसा सूक्ष्म कृमियों के नष्ट होने के कारण होता है और जल्द ठीक हो जाता है। गंभीर स्थिति के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम रहेगी। उन्होंने कहा कि दवा न लेना सबसे बड़ा खतरा है।

कोडीन कफ सिरप सिंडिकेट मामले में जौनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मिलन फार्मा का मालिक गिरफ्तार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,03 फरवरी। यूपी के जौनपुर में कोडीन कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़े मामले में जौनपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सोमवार देर शाम एक आरोपीत को गिरफ्तार किया है। जिले में दर्ज इस संगठित ड्रग सिंडिकेट मामले में अब तक लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिससे पूरे नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद बढ़ गई है। गौरतलब है कि कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े इस मामले में जौनपुर जनपद में कुल दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें 22 आरोपी नामजद हैं। इस प्रकरण के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल को पहले ही सोनभद्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद जौनपुर पुलिस ने भोला जायसवाल को रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ भी की थी।

वहीं इस केस में नामजद एक अन्य आरोपी अंकित श्रीवास्तव को वाराणसी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी क्रम में जौनपुर पुलिस ने अपनी पहली सीधी गिरफ्तारी करते हुए मिलन फार्मा के मालिक शशांक मौर्या को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे सिंडिकेट की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है।पुलिस ने शनिवार को 22 आरोपित लोगो के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।वही मंगलवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए एसआईटी प्रमुख एवं सहायक पुलिस अधीक्षक गोल्डी गुप्ता ने बताया कि मिलन फार्मा के मालिक शशांक मौर्या को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से अहम जानकारियां मिल रही हैं।

संक्षिप्त खबरें

जाम को देखते हुए टेढ़ी बाजार–लता चौक पर नहीं चलेंगे ई–रिक्शा – मंडलायुक्त

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। मंडल आयुक्त राजेश कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में ई–रिक्शा के लिए रूट निर्धारित करने और टेढ़ी बाजार और लता मंगेशकर चौक तक अवैध रूप से हो रहे ई–रिक्शा को संचालन को बंद निर्देश दिए गए।आयुक्त ने अनियंत्रित एवं अवैध संचालन पर प्रभावी नियंत्रण एवं आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश नगर निगम एवं यातायात पुलिस को दिए हैं। बैठक में निर्णय हुआ कि दुकानदारों से वार्ता कर सुनिश्चित करें कि उनकी सामग्री दुकानों के बाहर न लगाई जाए, यदि कोई करता है तो सख्त कार्यवाही करें।नगर निगम को अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। होम स्टे योजना के संबंध में आयुक्त ने पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने और योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार के निर्देश दिए। विदेशी पर्यटकों के पहचान पत्र का विवरण भी होम स्टे के संचालकों को रखने के लिए निर्देश दिए गए।बैठक में आईजी प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे, एसएसपी गौरव ग्रोवर, प्राधिकरण उपाध्यक्ष अनुराज जैन, सीडीओ कृष्ण कुमार सिंह व नगर निगम, यातायात पुलिस, पर्यटन विभाग एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

वांछित आरोपी गिरफ्तार

अयोध्या।सोमवार को महिला थाना पुलिस ने कई माह से पुलिस के पकड़ से दूर वांछित आरोपी को बस्ती जिले से गिरफ्तार किया।इस संबंध में महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने बताया कि सूचना पर महिला उप निरीक्षक प्रिया ने कांस्टेबल चंद्रभान तथा महिला कांस्टेबल सरिता सिंह के साथ वांछित आरोपी अरविंद गोस्वामी पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र गिरी निवासी ग्राम खदरा थाना दबौलिया जनपद बस्ती को नया घाट पुल बस्ती से गिरफ्तार किया।

रिटायर्ड कर्मियों के सम्मान में हुआ जीजीआईसी मे समारोह का आयोजन

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। यू0पी0 एजुकेशनल मिनिस्ट्रीयल आफीसर्स एसोसिएशन उ0प्र0, जनपद इकाई अयोध्या द्वारा सेवानिवृत हुए शैलेन्द्र वर्मा, वैयक्तिक सहायक, कार्यालय संयुक्त शिक्षा निदेशक,तथा हरिशंकर सैनी, प्रधान सहायक, राजकीय बालिका इण्टर कालेज,पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुके परिचारक रामजी यादव के सम्मान मे राजकीय इंटर कॉलेज में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।इस मौके पर वहां पर उपस्थित संगठन के पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों ने सेवानिवृत हुए कर्मचारी द्वारा विभाग को दिए गए सेवाओं के बारे में प्रशंसा किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना किया।इस मौके पर वहां पर मौजूद संगठन के पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों ने सेवानिवृत हुए कर्मियों को शाल, मोमेन्टो, रामनामी पटका एवं पुष्पगुच्छ देकर सेवानिवृत्त कार्मिकों का अभिवादन किया गया।इस अवसर पर आशुतोष पति त्रिपाठी, अजय शुक्ल, सत्येन्द्र नाथ शर्मा, राजेन्द्र यादव, प्रकाश चन्द्र यादव, संजय श्रीवास्तव, शाजिया रिजवी, अंजलि चौरसिया, उमाकान्त मिश्रा, मो0 शरीफ अन्सारी, अशोक मिश्रा, प्रदीप कुमार, रवीन्द्र नाथ जोशी, सन्तोष कुमार, सन्तोष, सन्तोष श्रीवास्तव, रामबिलास यादव, आशीष कुमार, मोती लाल मौर्य, योगेश कुमार, रोहित, प्रियंका पासवान, अमित तिवारी, गायत्री, पूजिता, सचिन सिंह, मनोज कुमार दूबे, शैलेश स्वरूप, धीरेन्द्र कुमार, अभय मौर्या, सौरभ यादव, विकास गुप्ता एवं जनपदीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष आनन्द यादव, मंत्री नीरज सिंह, उपाध्यक्ष निशा मिश्रा व कोषाध्यक्ष सागर यादव उपस्थित रहे।

श्री राम चिकित्सालय में तैनात फार्मासिस्ट को बस्ती पुलिस ने लिया हिरासत मे

अयोध्या।श्रीराम अस्पताल में कार्यरत फार्मासिस्ट रामप्रीत वर्मा को एक सप्ताह पहले हुई हत्या से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में पुलिस ने हिरासत में लिया है।जिसके चलते श्रीराम चिकित्सालय मे हडकंप मच गया। जानकारी के मुताबिक परशुराम पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें मंगलवार तड़के करीब चार बजे उनके आवास से हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए साथ ले गई।जानकारी के अनुसार, पड़ोसी जनपद बस्ती के पकौली थाना क्षेत्र में दर्ज अपहरण और हत्या के प्रयास के मामले में रामप्रीत वर्मा को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लिया गया है।इस मामले में अपहरण में प्रयुक्त टाटा नेक्सन कार भी फार्मासिस्ट की निशानदेही पर बरामद की गई है।कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने श्रीराम अस्पताल परिसर में स्थित फार्मासिस्ट के कार्यालय की भी गहन जांच की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगे हैं।

उद्योग-अकादमिक तालमेल से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर : प्रो. प्रदीप कुमार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के श्केन्द्रीय प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट सेलश (ब्ज्च्ब्) में विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य और स्वावलंबन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए

रोजगार अवसर कार्यक्रमश का मंगलवार को आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी एसएनजे टोयोटा ने विश्वविद्यालय के स्नातक एवं परास्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों का साक्षात्कार कर उन्हें श्सेल्स ऑफिसरश पद के लिए चयनित किया। चयन प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहीं एसएनजे टोयोटा, जौनपुर की ग्रुप हेड (मानव संसाधन) सारिका सिंह ने बताया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में युवाओं के लिए करियर की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, ष्हमारा उद्देश्य केवल रोजगार देना ही नहीं, बल्कि युवाओं को उद्योग की आधुनिक

आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना है। भविष्य में भी ऐसे आयोजन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर किए जाएंगे। सीटीपीसी परिसर में आयोजित इस साक्षात्कार प्रक्रिया में बड़ी संख्या में छात्र–छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। कंपनी के प्रतिनिधियों ने अभ्यर्थियों की संवाद क्षमता (ब बाजार की समझ और ग्राहक सेवा कौशल का सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया। कार्यक्रम के समापन पर सीटीपीसी के निदेशक प्रो. प्रदीप कुमार ने एसएनजे टोयोटा की टीम का आभार प्रकट किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार प्रयासरत है कि विद्यार्थियों को कैंपस से ही प्रतिष्ठित संस्थानों में नियुक्ति मिल सके। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच ऐसा जीवंत सहयोग प्लेसमेंट तंत्र को और अधिक सशक्त बनाता है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के डॉ. नितेश जायसवाल, डॉ. सुशील कुमार, श्याम त्रिपाठी सहित छात्र सदस्य दिव्यांशु, संजय, रुद्रांश चतुर्वेदी, श्रेया मिश्रा और गौरव प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

एसआईआर प्रक्रिया को लेकर फैली अफवाहों का एडीएम ने किया खंडन, कहा बिना हस्ताक्षर फॉर्म पूरी तरह अमान्य : परमानन्द झा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर,03 फरवरी। यूपी के जौनपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सोमवार से सोशल मीडिया पर यह चर्चा जोरों पर है कि एक विशेष राजनीतिक पार्टी द्वारा फॉर्म–7 भरवाकर बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे मतदाताओं के नाम सूची से काटे जा रहे हैं। इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक दिन पूर्व सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करै प्ट प्रक्रिया पर सवाल भी उठाए थे। इस मामले में जानकारी देते हुए मंगलवार को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) परमानंद झाँ ने स्पष्ट रूप से इसे अफवाह बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का खंडन करते हुए कहा

कि यह पूरी तरह झूठ और निराधार हैं। एडीएम ने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार का फॉर्म यदि बीएलए द्वारा दिया जाता है तो उस पर हस्ताक्षर अनिवार्य है। बिना हस्ताक्षर वाला कोई भी फॉर्म प्रशासन के लिए पूरी तरह अमान्य और रद्दी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कुछ राजनीतिक दलों के लोग बिना हस्ताक्षर किए हुए फॉर्म दिखाने आए थे, लेकिन ऐसे फॉर्म का कोई कानूनी या प्रशासनिक महत्व नहीं है और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। एडीएम परमानंद झाँ ने मतदाताओं से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें और किसी भी संशय की स्थिति में सीधे प्रशासन या संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करें।

संक्षिप्त खबरें

तारुन और मयाबजार दो विकास खंडो में घर–घर खिलाई जाएगी फाइलेरिया से बचाव की दवा – सीएमओ

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जनपद के तारुन और मयाबजार दो विकासखंडों में 10 से 28 फरवरी तक सामूहिक दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा।दोनों ब्लॉकों की कुल लक्षित आबादी लगभग 4.93 लाख है। इस बात की जानकारी मंगलवार को सीएमओ डॉ देवेंद्र कुमार भिटौरिया ने अपने कार्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान बताई।उन्होंने बताया कि अभियान के लिए 87 सुपरवाइजर और 495 टीमें गठित की गई हैं जो घर–घर जाकर पात्र व्यक्तियों को अपने सामने दवा सेवन कराएंगी।सभी ग्राम पंचायतों में अभियान का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वयं दवा सेवन कर लोगों को प्रेरित करते हुए किया जाएगा।बताया कि फाइलेरिया उन्मूलन की सबसे बड़ी चुनौती लोगों की फाइलेरिया से बचाव की दवा सेवन में संकोच और भ्रांतियाँ हैं।कई लोग स्वयं को स्वस्थ समझकर दवा सेवन से इनकार कर देते हैं या दुष्प्रभाव की भ्रांति से पीछे हट जाते हैं। मीडिया सही सूचना और भरोसा देकर लोगों को दवा सेवन के लिए प्रेरित कर सकता है।सीएमओ ने बताया कि फाइलेरिया केवल स्वास्थ्य समस्या नहीं बल्कि सामाजिक–आर्थिक संकट भी है। जनपद में वर्तमान में 1334 हाथीपांव और 11 हाइड्रोसील मरीज पंजीकृत हैं। यह बीमारी व्यक्ति को आजीवन कमजोर बना देती है जिससे पूरे परिवार की आजीविका प्रभावित होती है।इस मौके पर एसीएमओ एवं बीवीडी नोडल अधिकारी डॉ. पीसी भारती ने बताया कि हालिया नाइट ब्लड सर्वे में तारुन और मयाबजार संवेदनशील पाए गए हैं। इसलिए यहां की आबादी को फाइलेरिया से बचाव के लिए 12.32 लाख डीईसी, 12.32 लाख आइवरमेक्टिन और 4.93 लाख एल्बेंडाजोल टैबलेट राज्य मुख्यालय से उपलब्ध कराई गई हैं।

गर्भवती महिलाओं, दो वर्ष से छोटे बच्चों और गंभीर रोगियों को छोड़कर सभी को दवा स्वास्थ्य कर्मियों के सामने खिलाई जाएगी ताकि संक्रमण की श्रृंखला टूट सके।सीफार के प्रतिनिधि ने बताया कि फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है,जिसके सूक्ष्म कृमि मच्छरों द्वारा दूसरों में फैलते हैं। इसके लक्षण कई वर्षों बाद हाथ–पैर या जननांगों में सूजन के रूप में दिखते हैं। इससे बचाव की दवाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और डबल्यूएचओ से प्रमाणित हैं। दवा सेवन के बाद हल्का बुखार या चक्कर आना सामान्य है ऐसा सूक्ष्म कृमियों के नष्ट होने के कारण होता है और जल्द ठीक हो जाता है। गंभीर स्थिति के लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम रहेगी। उन्होंने कहा कि दवा न लेना सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि एक संक्रमित व्यक्ति से अनजाने में उसके साथ साथ पूरे गांव में संक्रमण फैल सकता है।जिला मलेरिया अधिकारी मंजुला आनंद ने बताया कि प्रशिक्षण, अंतरविभागीय समन्वय और ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन पूरा हो चुका है। पीसीआई और सीफार प्रतिनिधियों ने मीडिया से अपील की कि वे लोगों तक यह संदेश पहुँचाएँ कि फाइलेरिया दवा से रोका जा सकता है और दवा न न सेवन करने पर यह पीढ़ियों की समस्या बनी रह सकती है।इसके अलावा राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस दिनांक 10 फरवरी 2026 को एवं शेष छूटे हुए बच्चों को मॉप अप राउंड दिनांक 13 फरवरी 2026 को एल्बेंडाजोल दवा खिलाई जाएगी।इस अभियान के अंतर्गत अयोध्या जिले के दो ब्लॉक मया बाजार एवं तारुन को छोड़ कर शेष 9 ब्लॉकों एवं शहरी क्षेत्र में अल्बेंडोजोल की दवा खिलाई जाएगी। इस अभियान में 1वर्ष से 19 वर्ष तक जनपद के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर अल्बेंडोजोल की गोलियां खिलाई जायेंगी।

हैदरगंज पुलिस ने आवासीय प्लाट को ढहाने वाली जेसीबी मशीन को किया बरामद

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर अयोध्या)

अयोध्या। थाना हैदरगंज पुलिस ने आवासीय प्लाट को रात में ढहाने वाली जेसीबी मशीन पुलिस ने बरामद कर लिया। परंतु चालक फरार होना बताया जा रहा है।ध्वस्त करने वाले 14 आरोपियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में पुलिस दो को पड़कर जेल भी भेज चुकी है।वहीं पुलिस का जांच का दायरा बढ़ने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया क्योंकि साजिश रचने मे कई सम्मानित लोगों के नाम की चर्चाओ ने जोर पकड़ ली है। जिन पर पुलिस शिकंजा कस सकती है। घटना थाने से महज सौ मीटर की दूरी पर होने के चलते पुलिस इसे चौलेंच स्वरूप मानकर कानूनी कार्यवाही करने में जुटी है। थाना क्षेत्र हैदरगंज के इमिलिया ग्राम पंचायत में थाने के पास हैदरगंज भीटी मार्ग के किनारे केरा लाल खा, चौबेपुर मलावन निवासी दुर्गावती पत्नी स्वर्गीय कृष्ण कुमार का आवासीय निर्माणधीन प्लांट की बाउंड्री वॉल व अंदर बने ऑफिस उसमें रखे कुर्सियां मेज आदि को 26 जनवरी की रात जेसीबी मशीन से ढहा कर ध्वस्त कर दिया था।इसकी जानकारी होने पर प्लांट की मालकिन की लिखित तहरीर पर हैदरगंज थाने की पुलिस ने तोड़फोड़ के साथ जान से मारने की धमकी आदि सहित कई अपराधिक गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर ध्वस्त करने वालों की तलाश शुरू कर दी थी। वही दो आरोपियों को पड़कर चालान करके घटना मे शामिल मशीन की तलाश में जुटी थी। और थाना क्षेत्र के करौ गांव से मशीन बरामद कर ली।परंतु चालक भाग निकला। घटना के संबंध में थानाध्यक्ष विवेक राय ने बताया कि क्षेत्र में इस तरह दबगई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।कानून का राज चलेगा और कहां बाउंड्री वॉल ध्वस्त करने वाली जैसी मशीन बरामद कर ली गई है। मुकदमे के विवेचक उप निरीक्षक अरविंद सिंह ने बताया की थाने के बगल प्लांट होने की दशा में किसी की गिराने की हिम्मत नहीं करनी थी।परंतु कुछ स्थानीय सम्मानित लोगों के साजिश से गिराया गयाहै। ऐसी साजिश रचने वाले लोगों की चिन्हित किया जा रहा है।उनके विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कर उन्हें और चालक को पड़कर जेल भेजा जाएगा। क्षेत्र में कानून का राज चलेगा।और वही कार्यवाही की जा रही है।जल्द ही अन्य लोगो की गिरफ्तारी की जाएगी।

शीघ्र से शीघ्र दिव्यांग कार्यालय मे पात्र संस्था करे आवेदन - डीएम

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर अयोध्या)

अयोध्या।प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर, शिक्षित और सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में निरंतर ठोस कदम उठा रही है।राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के पुनर्वासन को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान प्रदान करने के लिये आवेदन मांगे हैं।इस बात की जानकारी देते हुए डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया पात्र संस्था जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण करण कार्यालय मे 4 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।यह योजना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के तहत संचालित है जिसके अंतर्गत परिभाषित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को कवर किया गया है। हालांकि, मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण दिव्यांगजनों को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वासन के माध्यम से समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को निम्नलिखित सात परियोजनाओंध्कार्यक्रमों के संचालन हेतु सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा।इनमें अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, डे–केयर सेंटरध्प्री–प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल स्तर के विशेष विद्यालयों का संचालन,जूनियर हाईस्कूल स्तर तक के विद्यालयों का संचालन, हाईस्कूल स्तर तक के विशेष विद्यालयों का संचालन, कौशल विकास कार्यक्रम (न्यूनतम दो एवं अधिकतम चार ट्रेड) तथा पाठ्य सामग्री विकास एवं पुस्तकालयों का संचालन शामिल है। इन परियोजनाओं के माध्यम से दिव्यांग बच्चों एवं युवाओं को प्रारंभिक देखभाल, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।पात्र संस्था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के अंतर्गत पंजीकृत वे स्वैच्छिक संगठन,जिन्हें संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव है तथा जो शासन द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हैं।बताया कि इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र होंगे।योजना से संबंधित कार्यकारी आदेश, दिशा–निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट ीजजचरूध्ध्नचीूक.हवअ.पद से प्राप्त किया जा सकता है।इसके पश्चात जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी चंद्रेश त्रिपाठी द्वारा प्रस्तावों को डीएम कार्यालय की संस्तुति के साथ 05 फरवरी 2026 तक निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा।बताया कि प्रदेश सरकार की यह योजना दिव्यांगजनों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। स्वैच्छिक संस्थाएं समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करें, जिससे पात्र दिव्यांगजनों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। जिला प्रशासन पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।बताया कि योगी सरकार की यह पहल स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से जमीनी स्तर पर दिव्यांगजनों तक सुविधाएं पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगी।शिक्षा, कौशल विकास और पुनर्वासन से जुड़ी यह योजना दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक **देश की उपासना**

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।